लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3648
17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

कताई मिलों के लिए योजना

3648. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यवतमाल जिले में सूत कताई मिलों की स्थापना के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यवतमाल के कपास क्षेत्र में उक्त मिलों की स्थापना के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के आधार पर कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यवतमाल में किसानों को कपास का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए कोई सहायता नीति कार्यान्वित की है और यदि हां, तो उसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) यवतमाल में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं; और

(ङ) क्या यवतमाल जिले में उक्त मिलों के लिए आवश्यक अवसंरचना के विकास हेतु कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): जी, नहीं।

(ग): सरकार, किसानों के लिए उचित पारिश्रमिक को सुनिश्चित करने के लिए कपास हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना क्रियान्वित कर रही है। कपास मौसम वर्ष 2024-25 के लिए, भारत सरकार ने कपास के एमएसपी में पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% तक की वृद्धि की है। दिनांक 09.12.2024 तक, सीसीआई ने महाराष्ट्र में लगभग 19.16 लाख क्विंटल कपास (3.65 लाख गांठ के बराबर) की खरीद की है, जिससे लगभग 0.57 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से 0.40 लाख गांठ यवतमाल जिले में खरीदी गई है।

(घ) और (ड़): सरकार वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं/पहलों को क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख पहलों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क, उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम), समर्थ- वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना, जूट (आईसीएआरई- उन्नत खेती और बेहतर रेटिंग प्रक्रिया), सिल्क समग्र 2.0, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम, एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) आदि शामिल हैं।

***